

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या — /VII-1/08-541 उद्योग/07
देहरादून: दिनांक 03 जुलाई, 2008

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास हेतु भूमि आबंटन के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों/नीति/नियमों को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास हेतु भूमि आबंटन से संबंधित निम्नवत् नीति तत्काल प्रभाव से प्रख्यापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास हेतु भूमि आबंटन नीति।

1. यह नीति न तो केवल औद्योगिक विकास हेतु है और न ही केवल भूमि आबंटन हेतु बनायी गयी है अपितु दोनों को समान सामन्जस्य करते हुये एक उचित नीति प्रतिपादित की जा रही है, ताकि प्रदेश में उद्योगों को औद्योगिक विकास के नाम पर कम मूल्य में भूमि न दी जा सके।
2. उक्त दोनों बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एक औद्योगिक भूमि आबंटन नीति प्रतिपादित की जा रही है, जो निम्न प्रकार है:-
3. औद्योगिक विकास:-

सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि आबंटन नीति इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये प्रतिपादित की जा रही है कि प्रदेश में ऐसे उद्योगों को ही प्रोत्साहन दिया जायेगा, जो नई तकनीकी का प्रयोग करेंगे, उत्तराखण्ड में बेरोजगारों को समुचित मात्रा में रोजगार उपलब्ध करायेंगे, साथ ही उद्योग, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हो तथा प्रदेश की पिछड़े क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। ऐसे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जायेगा जो कि औद्योगिक नीति 2003 के अन्तर्गत थ्रस्ट सेक्टर के अन्तर्गत आते हैं।

4. औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक भूमि आबंटन नीति अवांछनीय उद्योगों एवं तत्वों को हतोत्साहित करेगी।
5. भूमि आबंटन:-

किसी भी नियत तिथि को प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु कुल उपलब्ध भूमि का 25 प्रतिशत ऐसे उद्योगों हेतु आरक्षित किया जायेगा, जो कि लघु एवं मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, उनके लिये भूमि आबंटन की अधिकतम सीमा 5 एकड़ होगी। इस

भूमि का मूल्य सम्बन्धित क्षेत्र में पूर्व में अधिकतम बोली राशि का 125 प्रतिशत निर्धारित होगा।

6. कुल उपलब्ध भूमि का 25 प्रतिशत ऐसे उद्यमियों हेतु आरक्षित किया जायेगा, जो कि तकनीकी रूप से उन्नत किस्म के नवीनतम उत्पाद का निर्माण करेंगे तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमिता का विकास करने में सहायक होंगे, साथ ही स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेगे तथा उत्तराखण्ड राज्य में थ्रस्ट सैक्टर से सम्बन्धित उद्योग लगायेंगे। इस भूमि का मूल्य सम्बन्धित क्षेत्र में पूर्व में अधिकतम बोली राशि का 125 प्रतिशत निर्धारित होगा।

7. बाकी अवशेष 50 प्रतिशत भूमि को "सेलैक्टिव लॉटरी" के माध्यम से आवंटित किया जायेगा तथा इसका न्यूनतम मूल्य सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित किये जाने वाले भू-खण्ड के समकक्ष क्षेत्रफल के भू-खण्ड हेतु अधिकतम बोली राशि का 125 प्रतिशत निर्धारित होगा।

उक्त लॉटरी में निम्नलिखित पात्रता रखने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी।

- (अ) ऐसे उद्योग जिनमें शत प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश हो।
- (ब) ऐसे उद्योग जिनका विदेशी स्वामित्व वाले उद्योग जिनका ग्रुप वार्षिक टर्नओवर (Turn over) लगभग 2,000 करोड़ या अधिक हो तथा न्यूनतम 75 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित हो।
- (स) ऐसी भारतीय कम्पनियां जिनका वार्षिक ग्रुप टर्नओवर (Turn over) लगभग 1000 करोड़ या अधिक हो तथा न्यूनतम निवेश रु० 50 करोड़ का पूंजी निवेश किया जाना प्रस्तावित हो।

9. उद्यमियों को उक्त आबंटन नीति के अन्तर्गत भूमि इस प्रतिबद्ध के साथ आवंटित की जायेगी कि वह आवंटित भूमि पर निर्धारित समय में उद्योग स्थापित करें अन्यथा उद्यमी को एक बार सुनवाई का अवसर देते हुए प्रदेश सरकार को यह अधिकार होगा कि वह भूमि का आबंटन निरस्त कर भूमि वापस प्राप्त कर लें।

10. आबंटन प्रक्रिया:-

औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सभी प्राधिकृत विभागों में लम्बित भूमि आबंटन हेतु आवेदन-पत्र तथा किसी भी कार्य दिवस में प्राधिकृत विभाग में भूमि आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को साप्ताहिक रूप से उपरोक्त भूमि आबंटन नीति के अनुसार आबंटन हेतु स्वीकृति प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

स्वीकृत प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष और सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

अध्यक्ष	—	मा0 औद्योगिक विकास मंत्री।
उपाध्यक्ष	—	मुख्य सचिव।
सदस्य	—	अपर मुख्य सचिव/अवस्थापना विकास आयुक्त।
सदस्य	—	प्रमुख सचिव/सचिव औद्योगिक विकास।
सदस्य	—	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त।
सदस्य	—	प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय।
सदस्य	—	निदेशक, उद्योग।
सदस्य सचिव	—	प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल।

11. इसके अतिरिक्त अन्य प्रक्रिया एवं शर्तें पूर्व जारी नियम/नीति एवं प्रक्रिया की भांति यथावत रहेंगी।

पी0सी0 शर्मा
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 2513 (1)/VII-1/08-541 उद्योग/07 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक उद्योग, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
8. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।